

RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

Key Point

DATE
सितम्बर
14
2024

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index



By Ankit Avasthi Sir

National Security Strategies Conference-2024



नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दो-दिवसीय **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन - 2024** का उद्घाटन किया।

- ✓ गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों** की सिफारिशों को ट्रैक करने के लिए **डैशबोर्ड** का शुभारंभ किया, जिसे **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** ने विकसित किया है।

सम्मेलन का उद्देश्य:

- ✓ इस दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य **राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPOs)** के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर **राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों** का समाधान ढूँढने का रोडमैप तैयार करना है।
- ✓ सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा **पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों सम्मेलन** के दौरान प्रस्तावित किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार-विमर्श:

- ✦ इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, युवा पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श के माध्यम से **राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों** का समाधान ढूँढना है।
- ✦ वर्ष 2020 में आयोजित **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन** में प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि सम्मेलन को **हाइब्रिड मोड** में आयोजित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के बारे में:

- ✦ **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** की स्थापना वर्ष **1986** में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- ✦ इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और अपराध से संबंधित सूचनाएं प्रदान कर पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना था।
- ✦ ब्यूरो की स्थापना **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)** और **गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985)** की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

NCRB की प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- ✓ **यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) :** NCRB को **यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Sexual Offenders-NDSO)** को बनाए रखने और नियमित रूप से इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 - ✓ **साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल :** ब्यूरो को **ऑनलाइन साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** के तकनीकी और परिचालन प्रबंधन की केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक **बाल अश्लीलता, बलात्कार, या सामूहिक बलात्कार** से जुड़े अपराधों के सबूत जैसे वीडियो क्लिप अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
 - ✓ **अंतर-प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS):** NCRB को **Inter-operable Criminal Justice System (ICJS)** के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह प्रणाली, देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तंभों को जोड़ने का प्रयास करती है। इसमें पाँच मुख्य स्तंभ शामिल हैं:
 - ✦ **पुलिस (अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली)**
 - ✦ **फोरेंसिक लैब (ई-फोरेंसिक)**
 - ✦ **न्यायालय (ई-कोर्ट)**
 - ✦ **लोक अभियोजन (ई-अभियोजन)**
 - ✦ **जेल प्रशासन (ई-जेल)**
- NCRB के प्रमुख प्रकाशन:**
1. **क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट**
 2. **आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट**
 3. **जेल सांख्यिकी**
 4. **भारत में गुमशुदा महिलाएं और बच्चे**

KVIC और NIFT ने 'खादी उत्कृष्टता केंद्र-2.0' समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) ने एक महत्वपूर्ण समझौता जापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता जापन के तहत, खादी उत्कृष्टता केंद्र 2.0 (COEK-2.0) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप खादी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और इसके घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच को बढ़ाना है।

एनआईएफटी इस समझौते के माध्यम से खादी को और अधिक लोकप्रिय और विपणन योग्य बनाने में सहयोग करेगा। इसके अंतर्गत खादी संस्थानों को प्रशिक्षण, डिजाइनिंग, भवन नवीनीकरण और नए खादी उत्पादों के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी।

समझौता:

दिल्ली के राजघाट स्थित KVIC कार्यालय में समझौता जापन पर हस्ताक्षर हुए।

COEK-2.0 के तहत प्रमुख योजनाएं:

- ✓ नई दिल्ली में एक हब सेंटर और बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता, गुवाहाटी, पंचकूला, हैदराबाद, और भुवनेश्वर में स्पोक सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- ✓ खादी ज्ञान पोर्टल, फैशन शो, प्रदर्शनी, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजाइन कैटलॉग और सुपर-टेक्नोलॉजी बिक्री आउटलेट्स जैसे कदम उठाए जाएंगे।
- ✓ असम में एक रंगाई स्टूडियो और खादी ज्ञान पोर्टल संस्करण-2.0 का अनावरण भी किया जाएगा।

खादी के लिए नई दिशा और रणनीतियाँ:

- ✦ यह साझेदारी 'खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
- ✦ COEK-2.0 खादी के नए स्टोर्स के निर्माण और डिजाइन में सहायता करेगा, KVIC के लिए रणनीति तैयार करेगा, और राज्य कार्यालयों के साथ समन्वय करेगा।
- ✦ इसके अंतर्गत खादी भवनों के लिए चयनित डिजाइन तैयार किए जाएंगे और खादी कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- ✦ खादी की गुणवत्ता और ब्रांड शक्ति को मजबूत करने के लिए, KVIC अगले तीन वर्षों में COEK के माध्यम से लगभग 25.17 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC):

- ✦ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) संसद के अधिनियमों (1956 के 61 वें अधिनियम, 1987 के अधिनियम 12, और 2006 के अधिनियम 10) द्वारा स्थापित एक विधिक संगठन है। इसे अप्रैल 1957 में स्थापित किया गया था और इसने अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल से कार्यभार ग्रहण किया। यह संगठन भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।



खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के उद्देश्य

- ✦ **आर्थिक उद्देश्य:** बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन
- ✦ **सामाजिक उद्देश्य:** रोजगार सृजन
- ✦ **वृद्ध उद्देश्य:** जनता में आत्मनिर्भरता और मजबूत ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना

मुख्य कार्य:

1. **समन्वय और योजना:** ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन करना।
2. **प्रशिक्षण और सहायता:** खादी और ग्रामोद्योग में लगे कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, सहयोगात्मक प्रयास की भावना उत्पन्न करना, कच्चा माल और औजारों का संग्रह बढ़ाना, और अनिर्मित माल के प्रशोधन के लिए सामान्य सेवा सुविधा का सृजन करना।
3. **विपणन प्रोत्साहन:** खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के विपणन के लिए सुविधा प्रदान करना और स्थापित विपणन अभिकरणों से संपर्क करना।
4. **अनुसंधान और विकास:** गैर-परंपरागत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के उपयोग के साथ-साथ उत्पादन तकनीकी और औजारों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और समस्याओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान करना।

भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में सफलता

भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रौद्योगिकी में सफलता प्राप्त की है, जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने सिलिकॉन आधारित प्रौद्योगिकी के बजाय धातु-कार्बनिक फिल्मों का उपयोग करके मेमरिस्टर अर्धचालक उपकरण विकसित किया है। यह नई सामग्री मेमरिस्टर को उस तरीके की नकल करने में सक्षम बनाती है, जिस तरह जैविक मस्तिष्क न्यूरॉन्स और सिनेप्स के नेटवर्क का उपयोग करके सूचना को संसाधित करता है।

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है?

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग या न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य को नकल करती है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना शामिल है, जो सूचना को संसाधित करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क और सिनेप्स का अनुकरण करता है।

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कैसे काम करती है?

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क (SNN) जैसे हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, जो जैविक मस्तिष्क की नकल करता है। SNN में कृत्रिम सिनेप्स से जुड़े नोड्स (स्पाइकिंग न्यूरॉन्स) होते हैं, जो सिग्नल स्थानांतरित करने के लिए एनालॉग सर्किटरी का उपयोग करते हैं। यह तरीका मानक कंप्यूटरों की बाइनरी प्रणालियों के बजाय असतत एनालॉग सिग्नल परिवर्तनों के माध्यम से डेटा को एनकोड करता है।

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लाभ:

- ✓ **अनुकूलनशीलता:** नई उतेजनाओं के प्रति जल्दी प्रतिक्रिया और वास्तविक समय में नई समस्याओं को हल करने की क्षमता।
- ✓ **घटना-संचालित संगणन:** केवल सक्रिय भाग ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।
- ✓ **उच्च प्रदर्शन:** न्यूरॉन्स में मेमोरी और प्रसंस्करण को एकीकृत किया जाता है, जिससे विलंबता कम होती है।
- ✓ **समानांतर प्रसंस्करण:** तेजी से संचालन के लिए विभिन्न न्यूरॉन्स में कई कार्यों को एक साथ करना।

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की चुनौतियाँ:

- बेंचमार्क और मानकों का अभाव
- सीमित पहुंच और सॉफ्टवेयर
- सटीकता में कमी

मस्तिष्क द्वारा सूचना का प्रसंस्करण:

न्यूरॉन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयाँ हैं। ये न्यूरॉन्स सूचना को मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों और शरीर के अन्य भागों के बीच पहुंचाते हैं। जब एक न्यूरॉन सक्रिय होता है या "स्पाइक्स" करता है, तो यह रासायनिक और विद्युत संकेतों को उत्सर्जित करता है। ये संकेत कनेक्शन बिंदुओं (सिनेप्स) के नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संवाद कर पाते हैं।



भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने शोध संस्थानों में से एक है। IISc बंगलुरु में स्थित है और यह देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है।

IISc क्यों महत्वपूर्ण है?

- 1. शोध और विकास:** IISc विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध करता है। इसका लक्ष्य मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से समाज के लिए नए ज्ञान और तकनीकों का विकास करना है।
- 2. शिक्षा:** IISc उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है और देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करता है। यहां स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
- 3. उद्योग सहयोग:** IISc उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है ताकि शोध परिणामों का व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। यह नई तकनीकों का विकास करने और भारत में उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करता है।

IISc के कुछ प्रमुख क्षेत्र:

- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के तहत वायुबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015 के कार्यान्वयन की दिशा में उठाया गया है।



वायुबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना के बारे में:

- ✓ **परियोजनाएँ:** गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 1000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएँ (प्रत्येक 500 मेगावाट) स्थापित की जाएंगी। इस पर कुल व्यय: ₹ 6853 करोड़ होगा।
- ✓ **वित्तपोषण:** VGF वित्त वर्ष 2031-32 तक प्रदान किया जाएगा।
- ✓ **बंदरगाह उन्नयन:** संभार-तंत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों का ₹ 600 करोड़ के व्यय से उन्नयन किया जाएगा।
- ✓ **कार्यान्वयन:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- ✓ **तकनीकी सहायता:** राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और परियोजनाओं की स्थापना और कमीशनिंग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- ✓ **पद्धति:** SECI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बोलीदाता का चयन किया जाएगा।
- ✓ **ग्रीनशू विकल्प:** अतिरिक्त 50 मेगावाट क्षमता का अति-आबंटन विकल्प उपलब्ध होगा।

अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में:

- ✦ **परिचय:** अपतटीय पवन ऊर्जा एक ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो समुद्र में स्थापित पवन टर्बाइनों से उत्पन्न होता है। यह पारंपरिक पवन ऊर्जा के समान है, लेकिन समुद्र में होने के कारण कई फायदे प्रदान करता है।
- ✦ **भारत में संभावनाएँ:** भारत की 7600 किमी लंबी तटरेखा और विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावनाएँ हैं।
- ✦ **महत्व:** यह 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है और भूमि उपलब्धता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।
- ✦ **चुनौतियाँ:** अपतटीय टर्बाइनों की प्रति मेगावाट लागत अधिक है, मजबूत संरचनाओं और नींव की आवश्यकता होती है, उच्च संक्षारण और समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव जैसी समस्याएँ हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRI)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRI) भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है जो नवीन और अक्षय ऊर्जा के विकास और स्थापना के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- ✦ **1970 के दशक** में तेल संकट के दौरान, तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई।
- ✦ **मार्च 1981 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग की स्थापना की गई।
- ✦ इसके बाद, **सितंबर 1982** में इसे जोड़कर ऊर्जा मंत्रालय में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग (डीएनईएस) का गठन किया गया।
- ✦ **अक्टूबर 2006 में मंत्रालय** का नाम बदलकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया।

मंत्रालय का विजन:

मंत्रालय का उद्देश्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है ताकि देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिले और ऊर्जा सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मंत्रालय का मिशन:

- ऊर्जा सुरक्षा
- स्वच्छ विद्युत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी
- ऊर्जा उपलब्धता और पहुँच

भारत के नैदानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में ICMR की पहल

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भारत के नैदानिक अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ICMR ने अपने नैदानिक परीक्षणों के नेटवर्क के पहले चरण के तहत कई प्रायोजकों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते और सहयोग

ये समझौते कई महत्वपूर्ण अनुसंधान पहल को दर्शाते हैं:

- ✓ **ऑरिजेन ऑन्कोलॉजी लिमिटेड** के साथ मिलकर **मल्टीपल मायलोमा** के लिए छोटे अणु पर अनुसंधान।
- ✓ **इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड** के साथ **जीका वैक्सीन** के विकास के लिए साझेदारी।
- ✓ **मायनवैक्स प्राइवेट लिमिटेड** के साथ **मौसमी इन्फ्लूएंजा वायरस वैक्सीन** परीक्षण का समन्वय।
- ✓ **इम्यूनोएक्ट** के साथ **क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया** के लिए **सीएआर-टी सेल थेरपी** का अध्ययन।

सरकार की प्रतिक्रिया:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ने इस सहयोग की सराहना की और इसे सस्ते और सुलभ उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह पहल भारत को **स्वास्थ्य सेवा नवाचार में वैश्विक नेता बनाने** में मदद करेगी।

ICMR का दृष्टिकोण:

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक ने कहा कि यह सहयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **भारत में नैदानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है। इस पहल से नैदानिक परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और **स्वदेशी अणुओं और अत्याधुनिक उपचारों के विकास** को बढ़ावा मिलेगा।

चरण 1 क्लिनिकल परीक्षण नेटवर्क:

इस नेटवर्क में भारत के चार प्रमुख संस्थान शामिल हैं:

- **केईएमएच और जीएसएमसी, मुंबई**
- **एसीटीआरईसी, नवी मुंबई**
- **एसआरएम एमसीएच एंड आरसी, कटनकुलथुर**
- **पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़**

ये संस्थान प्रत्येक परीक्षण स्थल पर मजबूत बुनियादी ढांचे और समर्पित जनशक्ति द्वारा समर्थित होंगे, ताकि नैदानिक परीक्षणों की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

परिणाम और उद्देश्य:

इन समझौतों से ICMR **ने उद्योग जगत के साथ अपनी साझेदारी** को मजबूत किया है। इससे भारत में नैदानिक परीक्षणों की क्षमता बढ़ेगी, **नई दवाओं के विकास में मदद मिलेगी, और सभी के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल** को बढ़ावा मिलेगा।



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR):

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) भारत में चिकित्सा अनुसंधान का शीर्ष निकाय है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ICMR का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए **जैव चिकित्सा अनुसंधान** को बढ़ावा देना है।

ICMR का कार्य:

- **चिकित्सा अनुसंधान:** ICMR विभिन्न रोगों जैसे कि **मलेरिया, डेंगू, टीबी, कैंसर आदि पर अनुसंधान** करता है।
- **नई दवाओं और वैक्सीन का विकास:** ICMR **नए दवाओं और वैक्सीन** का विकास करने के लिए काम करता है।
- **जन स्वास्थ्य कार्यक्रम:** ICMR जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को डिजाइन और लागू करने में मदद करता है।
- **मानव संसाधन विकास:** ICMR चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में **मानव संसाधन का विकास** करता है।

ICMR की संरचना:

ICMR एक विशाल संगठन है जिसमें कई **राष्ट्रीय संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र और सहयोगी केंद्र** शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान हैं:

- **राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (NARI)**
- **राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (NIMR)**
- **राष्ट्रीय टीबी अनुसंधान केंद्र (NTRC)**

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत हैं।

महत्वपूर्ण परिवर्तन:

- ✓ **ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)-आधारित ETC:** इस नए नियम में GNSS-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) के प्रावधान जोड़े गए हैं, जो कि 2008 के नियमों में संशोधन के रूप में लागू होंगे।
- ✓ **टोल लगाने के तरीके:** अब स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एपीएनआर) डिवाइस और GNSS ऑन-बोर्ड यूनिट (ओबीयू) को टोल संग्रह के तरीकों में शामिल किया जाएगा।
- ✓ **शून्य उपयोगकर्ता शुल्क:** यांत्रिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट वाहनों को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लगेगा।
- ✓ **विशेष लेन:** GNSS के लिए विशेष लेन बनाई जाएगी। इस लेन में प्रवेश करने वाले गैर-ओबीयू वाहनों को दोगुना शुल्क देना होगा।
- ✓ **फास्टैग की जगह:** GNSS-आधारित ETC का उद्देश्य भविष्य में फास्टैग के स्थान पर टोल संग्रह को सुविधाजनक बनाना है।

GPS-आधारित टोल सिस्टम (GNSS) क्या है?

GPS-आधारित टोल सिस्टम एक तरीका है जिसमें सैटेलाइट्स और वाहन में लगे ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग करके टोल की गणना की जाती है। यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल चार्ज करता है।

फायदे:

- ✦ टोल प्लाजा की ज़रूरत खत्म होती है।
- ✦ ट्रैफिक जाम कम होगा।
- ✦ ड्राइवर्स को टोल बूथ पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नए नियम:

- ✦ सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल नियमों में संशोधन किया है।
- ✦ यदि यात्रा की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है, तो टोल वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा।

GNSS तकनीक कैसे काम करेगी?

- ✦ **सिस्टम:** GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) से वाहन की स्थिति ट्रैक की जाएगी।
- ✦ **ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU):** वाहन में लगा डिवाइस, जो GPS का उपयोग करके टोल की गणना करेगा।
- ✦ **कैमरे:** हाईवे पर गैपट्रीज़ और CCTV कैमरे निगरानी के लिए लगाए जाएंगे।



GNSS तकनीक के फायदे

- ✦ टोल बूथ की ज़रूरत खत्म हो जाती है।
- ✦ ट्रैफिक जाम और इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत कम होती है।
- ✦ लगातार और सटीक ट्रैकिंग के साथ सही टोल की गणना होती है।

FASTag की तुलना में GNSS क्यों बेहतर है?

- ✓ **इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी:** टोल बूथ की ज़रूरत नहीं।
- ✓ **लगातार ट्रैकिंग:** सही टोल की गणना।
- ✓ **लचीलापन:** अलग-अलग टोल दरों और दूरी के लिए उपयुक्त।
- ✓ **कम प्रशासन:** ऑटोमेशन से मैनुअल काम कम होता है।

GNSS का टोल राजस्व पर प्रभाव:

- ✦ वर्तमान में NHA सालाना 40,000 करोड़ रुपये का टोल राजस्व जुटाती है।
- ✦ GNSS से यह राशि बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है।
- ✦ नए सिस्टम को FASTag के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा, और विशेष लेन बनाकर टोल कलेक्शन किया जाएगा।

भारतीय लाइट टैंक 'जोरावर' का फील्ड फायरिंग परीक्षण

13 सितंबर, 2024 को, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के सफल प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षणों की घोषणा की। यह टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है और अत्यधिक बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

फील्ड परीक्षणों का अद्वितीय प्रदर्शन:

- ✓ रेगिस्तानी इलाकों में किए गए फील्ड परीक्षणों के दौरान, लाइट टैंक ने असाधारण प्रदर्शन दिखाया और सभी निर्धारित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया। प्रारंभिक चरण में, टैंक के फायरिंग प्रदर्शन का सख्त मूल्यांकन किया गया, और यह निर्दिष्ट लक्ष्यों पर आवश्यक सटीकता प्राप्त करने में सफल रहा।

विकास में भारतीय उद्योगों की भूमिका:

- ✓ जोरावर को DRDO की इकाई, लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (CVRDE) द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है।
- ✓ इस परियोजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) सहित अनेक भारतीय उद्योगों ने विभिन्न उप-प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।

जोरावर लाइट टैंक के बारे में-

जोरावर लाइट टैंक भारत में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया एक हल्का टैंक है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और प्रमुख इंटीग्रेटर लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसका नाम प्रसिद्ध सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अधीन महत्वपूर्ण सैन्य सेवाएं दी थीं।

जोरावर टैंक की विशेषताएं:

- ✓ **वजन और गतिशीलता:** जोरावर लाइट टैंक का वजन अधिकतम 25 टन है, जो इसे हवाई मार्ग से आसानी से ले जाने योग्य बनाता है।
- ✓ **उच्च ऊंचाई और बहु-भूभाग संचालन :** यह टैंक ऊंचाई वाले इलाकों में हमला करने के साथ-साथ सीमांत और द्वीपीय क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है।

सभी परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, जोरावर लाइट टैंक को 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

क्वालिटी समर फनकैम्प 2024

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (NBQP) द्वारा आयोजित "क्वालिटी समर फनकैम्प" के दूसरे संस्करण के वर्चुअल पुरस्कार समारोह में भाग लिया। वर्ष 2024 की थीम: "सेफ्टी स्टार्स: शाइनिंग ब्राइट विद क्वालिटी"

- ✓ इस वर्ष की थीम "सेफ्टी स्टार्स: शाइनिंग ब्राइट विद क्वालिटी" ने सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व पर विशेष ध्यान दिया।
- ✓ इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के युवा नेताओं को प्रेरित करना था कि वे इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें।



छात्रों के लिए गुणवत्ता और नवाचार का मंच:

- ✓ क्वालिटी समर फनकैम्प का उद्देश्य भारत के भविष्य के कर्णधारों, यानी बच्चों, को विभिन्न क्षेत्रों जैसे भोजन, आवास, खेलौने, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्थिरता में गुणवत्ता मूल्यों से जोड़ना था।
- ✓ किडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रतियोगिताओं की श्रृंखला के माध्यम से सशक्त बनाया गया, जिसमें रचनात्मकता को गुणवत्ता और सुरक्षा के सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया।
- ✓ भविष्य में 10,00,000 छात्रों के इस फनकैम्प में भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रतियोगिताओं और व्यापक भागीदारी:

- ✓ इस वर्ष की प्रतियोगिताओं में भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 13,000 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया।
- ✓ प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन, ड्राइंग प्रतियोगिता, लघु वीडियो निर्माण और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां शामिल थीं।
- ✓ इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में गुणवत्ता के महत्व को समझाना था।

भविष्य की राह: गुणवत्ता और नवाचार की दिशा में:

- ✓ क्वालिटी समर फनकैम्प 2024 ने छात्रों की प्रतिभा और उनके द्वारा प्रदर्शित गुणवत्ता के मूल्यों को उजागर किया।
- ✓ इस कार्यक्रम ने भविष्य में गुणवत्ता के महत्व को फिर से स्थापित किया और प्रतिभागियों को याद दिलाया गया कि "सेफ्टी स्टार्स" के रूप में उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI):

- ✓ **स्थापना :** भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) की स्थापना 1996 में अंतर-मंत्रालयी कार्य बल, सचिवों की समिति और मंत्रियों के समूह में परामर्श के बाद यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों के आधार पर की गई।

स्वच्छता ही सेवा, 2024 अभियान

इस वर्ष, भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। 2024 का अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 'स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता' थीम के साथ आयोजित किया जाएगा और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के साथ इसका समापन होगा। वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष मनाए जा रहे 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देना है।



मत्स्यपालन विभाग की भागीदारी:

- ✓ देश के सभी प्रमुख विभाग एवं मत्स्यपालन विभाग इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।
- ✓ विभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां इस अवधि के दौरान स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी।
- ✓ इन गतिविधियों का उद्देश्य मछली बाजारों, बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों जैसे मत्स्यपालन से जुड़े बुनियादी ढांचे में स्वच्छता बनाए रखना है।

स्वच्छता जागरूकता और गतिविधियाँ:

- अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- इन कार्यक्रमों में मछली बाजार, मछली लैंडिंग केंद्र और फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स पर स्वच्छता के महत्व को समझाया जाएगा।
- इसके अलावा, मछुआरों और अन्य हितधारकों को स्वच्छ मत्स्यपालन प्रथाओं और अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विशेष सफाई अभियान:

- मत्स्यपालन क्षेत्र से जुड़े बड़े बंदरगाह, जलीय कृषि फार्म और जलाशय जैसे स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाए जाएंगे।
- इन अभियानों में प्लास्टिक कचरे, समुद्री मलबे और अन्य प्रदूषकों को हटाकर एक स्वच्छ और अधिक पर्यावरणीय संतुलित इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया जाएगा।

हितधारकों की भूमिका और जागरूकता:

- मत्स्यपालन विभाग अपने विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन और कचरे के निपटान की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करेगा।
- कचरे को अलग करने, खाद बनाने और पुनर्चक्रण पर विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे मत्स्यपालन गतिविधियों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया

अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया। यह नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जीत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक योगदान को उजागर करता है। यह वह भूमि है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था और जहां ऐतिहासिक सेलुलर जेल स्थित है।



औपनिवेशिक विरासत से प्रस्थान:

- ✓ श्री विजयपुरम का नया नाम औपनिवेशिक काल की विरासत से दूर जाने का संकेत देता है और अंडमान एवं निकोबार की समकालीन रणनीतिक भूमिका को भी रेखांकित करता है।
- ✓ यह द्वीपसमूह, जो एक समय चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- ✓ **चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति:**
 - चोल साम्राज्य के शासकों, विशेषकर राजराजा चोल (985-1014) और राजेंद्र चोल प्रथम (1014-1044) ने शक्तिशाली नौसेना का विकास किया।
 - उन्होंने आक्रामक सैन्य नीति अपनाते हुए प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग तक अपनी पहुंच बनाई और समुद्र में अपनी शक्ति स्थापित की।
- ✓ **बंगाल की खाड़ी का 'चोला झील' में परिवर्तन:**
 - चोल साम्राज्य ने अपनी सामरिक और नौसैनिक शक्ति से बंगाल की खाड़ी को 'चोला झील' में बदल दिया।
 - इससे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिला और कई व्यापारिक केंद्र, जैसे नागपट्टिनम, स्थापित किए गए।
- ✓ **महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान:**
 - राजराजा चोल ने कंडालुरसलाई जैसे क्षेत्रों में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आक्रमण कर वहां अपना नियंत्रण स्थापित किया। इ
 - सके साथ ही, उन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की।
 - राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने नौसैनिक अभियानों के तहत श्रीलंका के शेष हिस्से पर भी विजय प्राप्त की, जिससे पूरा द्वीप चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया।

सरकार ने बासमती चावल पर से न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) हटाया

भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बासमती चावल के निर्यात पर से न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) हटाने का निर्णय लिया है।

न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस):

न्यूनतम मूल्य या फ्लोर प्राइस किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत होती है, जिससे कम पर उस वस्तु या सेवा को बेचा नहीं जा सकता। इसे सरकार या किसी अन्य अधिकृत संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है।

न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के कारण:

- ❖ **किसानों की आय सुरक्षा:** कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना होता है।
- ❖ **उत्पादन को बढ़ावा देना:** कुछ मामलों में, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके सरकार किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है।
- ❖ **घरेलू उद्योगों की रक्षा:** न्यूनतम मूल्य से घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाया जा सकता है।

हालिया निर्णय:

- ✓ वर्तमान में, घरेलू चावल की पर्याप्त उपलब्धता और व्यापारिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर से न्यूनतम मूल्य को पूरी तरह से हटा दिया है।
- ✓ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अब बासमती चावल के निर्यात अनुबंधों की बारीकी से निगरानी करेगा ताकि किसी भी गैर-यथार्थवादी मूल्य निर्धारण और निर्यात प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

पृष्ठभूमि:

- ✓ अगस्त 2023 में, घरेलू चावल की कमी और गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात प्रतिबंध के कारण बासमती चावल की पहचान में संभावित गलत वर्गीकरण को रोकने के लिए 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था।
- ✓ अक्टूबर 2023 में विभिन्न व्यापार निकायों और हितधारकों के अनुरोध के बाद, इस न्यूनतम मूल्य को तर्कसंगत बना कर 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था।
- ✓ अब इस न्यूनतम मूल्य को पूरी तरह से हटा कर, भारत सरकार बासमती चावल के निर्यात को और बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

क्लस्टर बमों के नए प्रयोग से वैश्विक प्रतिबंध को खतरा

हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्लस्टर बम विस्फोटों से हजारों नागरिक मारे जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। इन गैरकानूनी हथियारों के नए प्रयोग से वैश्विक प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को खतरा हो रहा है।

क्लस्टर म्यूनिशन कोएलेशन द्वारा बनाई गई 100-पृष्ठीय रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में क्लस्टर बमों से होने वाली हताहतों में 93% नागरिक होंगे।

क्लस्टर म्यूनिशन क्या है?

क्लस्टर म्यूनिशन का उपयोग विद्युत चुम्बकीय संकेतों (जैसे रेडियो, रडार) के शत्रुतापूर्ण उपयोग को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है।

नवीनतम क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर के मुख्य तथ्य:

- ❖ दिसंबर 2023 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। इसमें 148 देशों ने समर्थन दिया, जिसमें 37 देश ऐसे थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। रूस ने इसका विरोध किया।
- ❖ 2023 में क्लस्टर बमों से हताहत होने वाले देशों की सूची में अजरबैजान, इराक, लाओस, लेबनान, मॉरिटानिया, म्यांमार, सीरिया, यूक्रेन, और यमन शामिल हैं।
- ❖ कुल 219 हताहतों में से 118 क्लस्टर बम हमलों से हुए और 101 अवशेषों से हुए।
- ❖ सम्मेलन में शामिल केवल 10 देश क्लस्टर हथियारों का उपयोग अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए कर रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या जर्मनी की है।
- ❖ 2023 में, दूषित राज्यों ने 83.91 वर्ग किमी भूमि को क्लस्टर बमों के अवशेषों से साफ किया और 73,348 अवशेष नष्ट किए।
- ❖ भारत, म्यांमार, रूस, और कोरिया गणराज्य में नए क्लस्टर बमों के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं।
- ❖ जुलाई 2023 और अप्रैल 2024 के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 155 मिमी आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों के पांच हस्तांतरण की अनुमति दी।
- ❖ 33 देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष कानून बनाए हैं।
- ❖ 22 देश इस सम्मेलन के लिए नए कानूनी उपाय बनाने की योजना बना रहे हैं, जबकि 43 देश अपने मौजूदा कानूनों को ही पर्याप्त मानते हैं।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!





APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH



Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499/-

**Validity
1 Year**

By Ankit Avasthi Sir



GA FOUNDATION

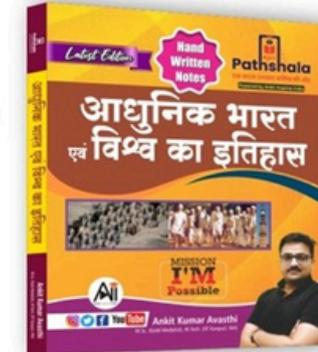
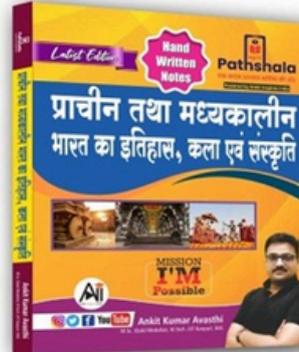
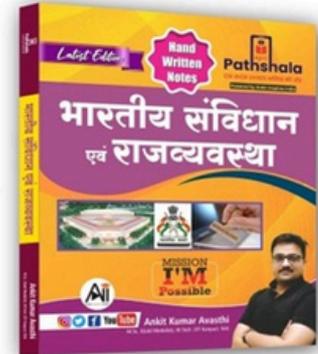
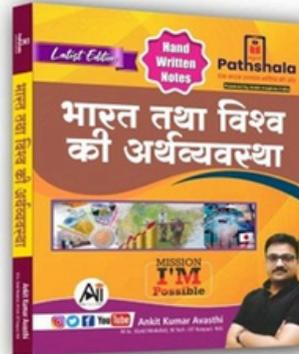
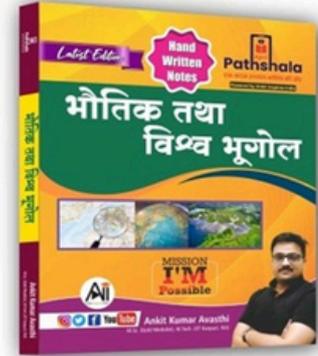
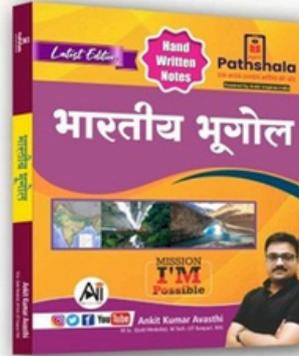
Hand Written
Notes


Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

RAS

FOUNDATION

वात्सल्य BATCH

Validity
1 Year

Re-launch

LIVE + RECORDED
BATCH



Price
4999/-



By Ankit Avasthi Sir